

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
07.02.2014	<p style="text-align: center;"><b>न्यायालय, समाहर्ता पूर्णियाँ</b> <b>नामान्तरण पुनरीक्षण वाद संख्या-86/2009</b></p> <p>1. मो० नसीम अख्तर, पिता-मो० कासीम 2. बीबी शाहिन बानौ उर्फ रूबी, पति-मो० नसीम अख्तर सा०-चकपरोरा, थाना-के०नगर, जिला-पूर्णियाँ —आवेदक</p> <p style="text-align: center;"><b>बनाम</b></p> <p>1. मो० जावेद आलम   पिता-मो० नूर आलम 2. मो० परवेज आलम   सा०-गणेशपुर टोला, चकपरोरा, थाना-के०नगर, जिला-पूर्णियाँ —विपक्षी सं०-1</p> <p>3. मो० अख्तरूल इस्लाम   पिता-स्व० शेख मो० रफीक 4. आलम आरा खान   5. मो० नूर आलम   दोनों के पिता-स्व० शेख मो० तौफीक 6. मो० सरफराज आलम   सा०-परोरा, थाना-के०नगर, जिला-पूर्णियाँ 7. मो० जमाल उर्फ बिट्टो, पिता-स्व० अली मोहम्मद 8. मो० कैयुम, पिता-मो० सिराज सा०-बनभाग, थाना-के०नगर, जिला-पूर्णियाँ —विपक्षी सं०-2</p> <p>9. राज्य —विपक्षी सं०-3</p> <p style="text-align: center;"><b>आ दे श</b></p> <p>आवेदक भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर द्वारा जमाबंदी सुधार वाद सं० 3/2005-06 एवं नामान्तरण अपील वाद सं० 22/2005-06 में दिनांक 24.09.2009 को पारित आदेश को निरस्त करने हेतु यह वाद प्रारंभ किया है। आवेदक का कथन है कि खाता सं० 144 खेसरा सं० 853 रकवा 20 डि०, खेसरा सं० 876 रकवा 31 डि० जमीन उभय पक्षों के बीच विवाद का विषय है। उपरोक्त खाता सं० 144 की जमीन मो० रफीक एवं मो० तौफीक के नाम दर्ज था। मो० रफीक एवं मो० तौफीक के बीच आपसी बंटवारा में खाता सं० 144 की जमीन मो० तौफीक के हिस्से में एवं खाता सं० 856 रकवा 58 डि० जमीन मो० रफीक के हिस्से में पड़ा। मो० रफीक के पुत्र अख्तरूल इस्लाम एवं पुत्री आलम आरा खान (विपक्षी सं० 3 एवं 4) ने दिनांक-16.02.2001 को अपनी जमीन निबंधित केवाला द्वारा मो० सलीम के पास बेच दिया और उक्त केवाला के समय साक्षी के रूप में मो० तौफीक के पुत्र विपक्षी सं० 5 एवं 6 थे। पुनः मो० तौफीक ने आवश्यकता पड़ने पर अपनी जमीन खाता सं० 144 रकवा 51 डि० जमीन आवेदक के पास बेच दिया तथा शेष जमीन अपने दोनों पुत्र विपक्षी सं० 5 एवं 6 को दान पत्र द्वारा दे दिया। आवेदक खरीदी गई जमीन का नामान्तरण अपने नाम करवा कर दखलकार हो गए। पुनः आवेदक खेसरा सं० 853 रकवा 10 डि० एवं खेसरा सं० 876 रकवा 15 डि० जमीन अपनी पत्नी आवेदिका सं० 2 के नाम लिख दिया। आवेदिका सं० 2 ने भी पति से प्राप्त जमीन का</p>	

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	<p>नामान्तरण अपने नाम करवा लिया। लम्बे अन्तराल के बाद विपक्षी सं० 3 एवं 4 ने खाता सं० 144 खेसरा सं० 853 एवं 876 रकवा 25 डि० जमीन विपक्षी सं० 1 एवं 2 के पास दिनांक-15.12.2004 को केवाला को केवाला कर दिया, जबकि विपक्षी सं० 3 एवं 4 को उपरोक्त जमीन बेचने का अधिकार नहीं था। क्योंकि उपरोक्त जमीन आपसी बटवारा में मो० तौफीक के हिस्से के हिस्से में था और मो० तौफीक ने उपरोक्त जमीन आवेदक के पास पूर्व में ही बेच दिया था। विपक्षी सं० 1 एवं 2 इस केवाला के आधार पर अंचलाधिकारी को नामान्तरण हेतु आवेदन दिया। लेकिन आवेदक के नाम जमाबंदी संख्या 1428 एवं 1910 दर्ज था। अतः अंचलाधिकारी द्वारा विपक्षी सं० 1 एवं 2 के आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया। विपक्षी सं० 1 एवं 2 ने विपक्षी सं० 7 एवं 8 के पक्ष में केवाला सं० 3257 एवं 3258 द्वारा दिनांक 06.04.2005 को प्रत्येक की 7 डि० 7½ कड़ी जमीन केवाला कर दिया। विपक्षी सं० 7 ने उपरोक्त केवाला के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन दिया और नामान्तरण वाद सं० 50/07/2005-06 द्वारा दिनांक 02.09.2005 को नामान्तरण आदेश पारित किया गया। उल्लेखनीय है कि विपक्षी सं० 7 ने केवाला सं० 3258 द्वारा केवाला करवाया लेकिन सुधार पर्ची में 6405 अंकित हैं। साथ ही आवेदक के नाम से दर्ज जमाबंदी सं० 1428 एवं 1910 को भी उक्त आदेश के आलोक में सुधार किया गया। इस नामान्तरण आदेश के विरुद्ध आवेदक भूमि सुधार उप-समाहर्ता, सदर के न्यायालय में नामान्तरण अपील वाद सं० 22/2005-06 दायर किया, जबकि विपक्षी सं० 1 एवं 2 ने भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर के न्यायालय में जमाबंदी सुधार वाद सं० 3/2005-06 प्रारंभ किया। निम्न न्यायालय द्वारा जमाबंदी सुधार वाद सं० 3/2005-06 को स्वीकृत किया गया। फलस्वरूप आवेदक इस न्यायालय में नामान्तरण पुनरीक्षण वाद सं० 45/2006 एवं 46/2006 दायर किया। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 04.12.2007 को दोनों वाद की सुनवाई साथ-साथ कर निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द करते हुए वाद को निम्न न्यायालय में पुनः जांच कर नियमानुकूल आदेश पारित करने हेतु वापस किया गया। पुनः निम्न न्यायालय द्वारा उभय पक्षों को सुनकर जमाबंदी सुधार वाद सं० 3/2005-06 को स्वीकृत करते हुए नामान्तरण अपील वाद सं० 22/2005 को खारिज करने का आदेश दिनांक-24.09.2009 को पारित किया गया। फलस्वरूप आवेदक निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध यह वाद प्रारम्भ किया है। निम्न न्यायालय द्वारा लम्बे समय से आवेदक के नाम जमाबंदी सं० 1428 एवं 1910 को नजर अंदाज किया गया। विपक्षी सं० 7 के नाम की गई जमाबंदी भी नियमानुकूल नहीं है। निम्न न्यायालय ने इस न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश का भी पालन नहीं किया। साथ ही स्वत्व के संबंध में फैसला करने का अधिकार निम्न न्यायालय को नहीं था। अतः आवेदक इस न्यायालय से अनुरोध करता है कि वाद की सुनवाई कर विधि सम्मत आदेश पारित करने की कृपा की जाय।</p> <p>विपक्षीगण का कथन है कि आवेदक द्वारा प्रारंभ किया गया यह वाद किसी भी दृष्टिकोण से निर्वहन योग्य नहीं है। इस न्यायालय द्वारा राजस्व पुनरीक्षण वाद सं० 45/2006 एवं 46/2006 में पारित आदेश के आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर द्वारा स्थल जांच कर नामान्तरण अपील वाद सं० 22/2005-06 एवं जमाबंदी सुधार अपील वाद सं० 3/2005-06 में पारित आदेश विधि सम्मत है। प्रश्नगत जमीन के खतियान के अनुसार शेख तौफीक एवं शेख मो० रफीक आलम दोनों के पिता-शेख मो० हनीफ दोनों भाई का बराबर का हिस्सा है। खाता नं० 144, खेसरा नं० 853, रकवा 20 डि०, खेसरा नं० 876, रकवा 31 डि० एवं खेसरा नं० 44, रकवा 16 डि०, कुल रकवा 67 डि० में दोनों भाई का 33½ डि० प्रत्येक को हिस्सा में प्राप्त था। शेख मो० तौफीक खेसरा नं० 44 का 16 डि०</p>	

IV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	<p>मो० नूर आलम एवं मो० सरफराज आलम दोनों के पिता शेख तौफीक को निबंधित हिब्बानामा दिनांक 25.03.1972 को कर दिया। मो० नूर आलम अपने पिता द्वारा प्राप्त हिब्बानामा के आधार पर अंचलाधिकारी, के०नगर को नामांतरण हेतु आवेदन किया। लेकिन शेख तौफीक ने आपत्ति आवेदन दिया कि उपरोक्त 16 डि० जमीन शेख तौफीक एवं रफीक आलम के नाम से है। अतः मात्र 08 डि० जमीन का हिब्बानामा वैध मानते हुए नामांतरण किया गया। शेख तौफीक द्वारा 16 डि० का हिब्बानामा कर देने के पश्चात मात्र 17½ डि० का हक खेसरा सं० 853 एवं 876 में प्राप्त था। किन्तु शेख तौफीक ने विवादित जमीन का कुल रकवा 51 डि० जमीन अपने भाई रफीक आलम को बताए बगैर आवेदक के पास बेच दिया। आवेदक नसीम अख्तर खरीदी गई जमीन का नामांतरण अपने नाम करवा लिया। उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत जमीन दो भाई शेख तौफीक एवं रफीक आलम के नाम से था लेकिन आवेदक ने नामांतरण वाद में रफीक आलम को पक्षकार नहीं बनाया और न ही अंचल कार्यालय न रफीक आलम को कोई सूचना दी। ऐसी स्थिति में उक्त नामांतरण आदेश मो० रफीक आलम या उनके उत्तराधिकारियों के लिए बंधनकारी नहीं था। आवेदक ने प्रश्नगत जमीन दिनांक 27.04.1978 को खरीदा लेकिन वर्ष 1990 ई० तक नामांतरण नहीं करवाया। मो० नसीम अख्तर एवं बीबी साहिन बानो आवेदकगण द्वारा धारित निबंधित केवाला से विपक्षी बंधित नहीं हैं। विवादित जमीन के स्वत्व पर आवेदक द्वारा सक्षम न्यायालय में किसी प्रकार का स्वत्व वाद दायर नहीं किया गया है। अतः विपक्षीगण इस न्यायालय से अनुरोध करता है कि आवेदक द्वारा प्रारंभ किए गए इस वाद को खारिज करने की कृपा की जाय।</p> <p>पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 27.01.2012 को उभय पक्षों को सुना गया। आवेदक का कथन है कि विपक्षी के द्वारा गलत ढंग से केवाला बनाकर दाखिल-खारिज हेतु आवेदन दायर किया गया। परन्तु उक्त जमीन में जमाबन्दीदार होने के बाबजूद भी आवेदक को पक्ष नहीं बनाया गया। निम्न न्यायालय में इसके विरुद्ध दायर वाद को विद्वान भूमि सुधार उप-समाहर्ता, सदर के द्वारा विपक्षी द्वारा दायर एक जमाबन्दी वाद के साथ गलत ढंग से जोड़कर आदेश पारित कर दिया गया। यह आदेश गलत है। इसके विरुद्ध समाहर्ता के न्यायालय में पुनरीक्षण दायर किया गया। इस वाद में विद्वान भूमि सुधार उप-समाहर्ता को स्थल जाँच कराकर आदेश पारित करने का निदेश हुआ। परन्तु विद्वान भूमि सुधार उप-समाहर्ता के द्वारा बिना किसी से जाँच किये वे खूद जाँच कर आदेश पारित किया गया, जो गलत है। साथ-साथ निम्न न्यायालय द्वारा केवाला की सत्यता के संबंध में भी आदेश हुआ है, जो निम्न न्यायालय के क्षेत्राधीन नहीं है।</p> <p>विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि इस न्यायालय में पारित आदेश के आलोक में विद्वान भूमि सुधार उप-समाहर्ता के द्वारा पूर्ण जाँच किया गया एवं उनका दखल-कब्जा पाया गया। इस कारण से उनके पक्ष में आदेश पारित किया गया, जो न्यास संगत है।</p> <p>उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन तथा उभय पक्षों को सुनने के बाद स्पष्ट होता है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है। इसमें किसी तरह की हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। इस निर्णय के साथ इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p>समाहर्ता, पूर्णिया</p>	